

OBSERVATIONS BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I had the painful duty, on the last occasion, to indicate that when, in the burst of emotion, an hon. Member exceeds decorum, there is a mechanism of rectification. The observations made by the hon. Member were expunged. They were hurtful to the chivalry and patriotism of a great son of the soil. Now, the observations having been expunged, the minimum respect a Member can pay is not to reiterate the same. The reiteration of what has taken place is something which hon. Members need to think about. Secondly, I am sure, security of every citizen as well as a Member is important and those concerned will take all steps in that direction, and there is no doubt about it. But these are issues wherein we need to moderate the temperature and make the climate a little more wholesome so that the societal dysfunction is contained. And, I made a fervent appeal on that day also but the reiteration was in a very aggravating form. I would urge the hon. Member to contemplate and appeal to Prof. Ram Gopal Yadav to bring his good influence, as a veteran parliamentarian, to bring quietus to this issue. And, quietus can be brought about only by respecting the Chair, and the Chair had found those observations unacceptable. I leave it to your wisdom. As regards security, every Member's security is important. We need to function on that principle. Let us not expand the debate now. I would have accommodated Jaya ji but I do not want to expand the debate now.

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, it is not on this issue.

MR. CHAIRMAN: Then, Madam, as per rules, right now, we have to take up the listed matters. Please send a chit to me. We will try to accommodate whatever you have to say under the permissible rules. Shri Radha Mohan Das Agrawal, please resume. Your time starts now.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION - *Contd.*

Need to improve the nutrition quality of food under Mid-day meal prograame

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, Mid-Day Meal एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रशंसनीय अभियान रहा है और इससे बच्चों को बहुत लाभ हुआ है। मैं

माननीय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूँ कि सितंबर, 2021 में उन्होंने 24 लाख आँगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मदरसा और मकतब को भी इस योजना में शामिल किया।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

इस योजना के तहत सारा अनाज, logistic, transport और किचन बनाने का खर्च, यह सब केन्द्र सरकार देती है। यहाँ तक कि खाना बनाने का 60 प्रतिशत हिस्सा भी भारत सरकार देती है। महोदय, इस योजना ने बच्चों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। ये बच्चों के कुपोषण की दर से संबंधित हैं। भोपाल में 55 परसेंट बच्चे wasted हैं; सुलिया, कर्णाटक में 26.5 परसेंट; बेंगलुरु में 52 परसेंट बच्चे malnourished हैं; इलाहाबाद में 65.53 परसेंट; वेल्लोर, तमिलनाडु में 83 परसेंट; बरेली, उत्तर प्रदेश में 38.4 परसेंट; करीमनगर, तेलंगाना में 29.3 परसेंट; कोझिकोड, केरल में 46.3 परसेंट; पूरे वेस्ट बंगाल में 22.8 परसेंट; लखनऊ में 57 परसेंट; कुरनूल में 63 परसेंट; वेस्ट बंगाल में 39.7 परसेंट; किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में 21.4 परसेंट; अहमदाबाद में 29.44 परसेंट; टिहरी गढ़वाल में 60.9 परसेंट; बरहामपुर, ओडिशा में 69 परसेंट; चंडीगढ़ में 73.3 परसेंट और संथाल परगना में 38.65 परसेंट हैं।

महोदय, ये आंकड़े यह बताते हैं कि जब यह मिड-डे-मील योजना शुरू हुई होगी, तो यह योजना बहुत इफेक्टिव रही होगी। मैं किसी की मंशा पर कोई अविश्वास प्रकट नहीं कर रहा हूँ। इस योजना को भारत सरकार एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत सहायता देती है और इसको लागू करने का काम विभिन्न राज्यों की मशीनरीज को करना होता है। मैं यह महसूस करता हूँ कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही एक योजना, जो एक समय में प्रभावी रही है, धीमे-धीमे अपना असर खो रही है और बच्चों के अंदर कुपोषण की दर में जो प्रभावी कमी होनी चाहिए, यह उनके अन्दर उस कमी को नहीं ला पा रही है। बच्चों का स्वास्थ्य देश के नौजवानों और वृद्धों के स्वास्थ्य का कारक होता है। अगर ये बच्चे आज कुपोषित होंगे, तो इस देश के बड़े नागरिक कुपोषित होंगे। इसलिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि वह सभी राज्य सरकारों से इस संदर्भ में बात करेगी, उनकी एक सामूहिक बैठक बुलाएगी कि इस योजना को किस प्रकार से और बेहतर तरीके से लागू किया जाए और अगर मशीनरीज सही तरीके से भोजन नहीं पहुँचा पा रही हैं, तो इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इस योजना के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में मैंने आपको जो रिपोर्ट दी है, वह बच्चों के डॉक्टर्स के द्वारा जो अध्ययन किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट दी है। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि पूरे देश के स्तर पर व्यापक सर्वे कराया जाए और कुपोषण की जो दर मिले, उसके हिसाब से या तो भोजन के अमाउंट में या इस योजना को लागू करने में, जो परिवर्तन जरूरी हैं, वे किये जायें, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Radha Mohan Das Agrawal: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Sanjay Yadav

(Bihar), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Sujeet Kumar, (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Rungwra Narzary (Assam), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shri Mithlesh Kumar (Uttar Pradesh), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Shri Mukul Balkrishna Wasnik, 'Demand to repeal Mahabodhi Vihar Act of 1949'.

Demand to repeal Mahabodhi Vihar Act of 1949

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (राजस्थान): उपसभापति महोदय, 12 फरवरी, 2024 से बोधगया में बौद्ध भिक्षु महासंघ ने इस मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन शुरू किया कि महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंप दिया जाना चाहिए। बोधगया एक विश्व स्तरीय बहुत पवित्र स्थान है। ढाई हजार साल पहले सिद्धार्थ गौतम को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने यहां एक भव्य विहार बनवाया था। पुरातत्ववेत्ता एलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई के दौरान इसकी खोज की, तब से यह स्थान विश्व के आकर्षण के साथ-साथ तथागत बुद्ध के बताए दुखों से मुक्ति का मार्ग भी बना। तथागत ने इसी भूमि से पूरे विश्व को शांति, प्रेम, मैत्री, शील और करुणा का मानवतावादी संदेश दिया, इसलिए बोधगया को दुनिया भर में आस्था और मानवतावादी विचार का पवित्र प्रतीक माना जाता है।

दुनिया में बौद्धों के आकर्षण का केंद्र, बोधगया में हर साल बड़ी संख्या में देश-विदेश से नागरिक आते हैं। यहीं से सम्यक सम्बुद्ध के मानवतावादी विचार पूरी दुनिया में फैले। बुद्ध-ज्ञान की ऊर्जावान भूमि, बोधगया महाबोधि महाविहार कई वर्षों से गैर-बौद्धों नियंत्रण में है, इसलिए बोधगया मुक्ति आंदोलन को न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में समर्थन मिल रहा है। कई राज्यों में 500 से ज्यादा संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। यह आंदोलन वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो गया है। बी.टी. एक्ट, 1949 के तहत बोधगया मंदिर प्रबंधन कमेटी में 9 सदस्य हैं। इन 9 सदस्यों में केवल 4 बौद्ध और 5 हिंदू, यानी गैर-बौद्ध हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वहां कई जातियां, धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। संविधान द्वारा यहाँ सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जैसे धार्मिक स्थानों का प्रबंधन उसी धार्मिक समुदाय का होता है, जिसका वह श्रद्धा-स्थान है, तो महाबोधि इसका अपवाद क्यों?

महोदय, 100 वर्षों से बोधगया को गैर-बौद्धों से मुक्त करने का संघर्ष चल रहा है। 2013 में इस कानून में संशोधन हुआ, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। मैं आज यहां सदन में केंद्र सरकार से यह